भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3092

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

3092. **श्री अरुण कुमार सागर:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संपूर्ण देश, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में पीएचसी में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार/जिला-वार भारी कमी है;

(ग) क्या उक्त केंद्रों के भवन जर्जर हालत में हैं और यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी - 2021-22 के अनुसार, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 31,053 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) कार्यरत हैं। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें स्वास्थ्य मानव संसाधन (डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) की भर्ती और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन या नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता शामिल है।

देश भर में स्वास्थ्य केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, पीएचसी में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की संख्या का विवरण आरएचएस 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

(घ) एनएचएम के अलावा, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) जैसी अन्य पहल भी शुरू की है। पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए धन प्रदान किया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट परिचर्या स्वास्थ्य प्रणालियों का क्षमता निर्माण, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत और नए संस्थानों का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा, स्थानीय सरकारों के माध्यम से प्राप्त 15 वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग भवन-रहित उप-केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी, ग्रामीण पीएचसी और उप-केंद्रों के स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में परिवर्तन के माध्यम से प्राथमिक देखभाल को मजबूत करने के लिए किया जाता है।

*****